खनन की आय से भरा खजाना, 1200 करोड़ रुपये के पार पहुंची कमाई

राज्य ब्यूरो, जागरण • देहरादून: उत्तराखण्ड के खनन विभाग ने राजस्व प्राप्ति के क्षेत्र में नया रिकार्ड स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में खनन विभाग ने 950 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 1217 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर सभी पुराने रिकार्ड तोड़ दिए हैं।

खनन विभाग की इस आय से कोषागार में 1130 करोड़ रुपये, जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में 80 करोड़ व एसएमईटी को सात करोड़ रुपये प्रदान किए गए। इससे पूर्व वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी विभाग ने 875 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 1041 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था।

45 अत्याधुनिक ई-चेक गेट स्थापित किए गए: मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर खनिज नीति एवं नियमावली का सरलीकरण किया गया, जिससे वैध खनन को बढ़ावा मिला और अवैध खनन, परिवहन व भंडारण पर प्रभावी रोक लगी। खनन पट्टों का आवंटन किया गया, जिससे राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि संभव हो सकी। माइनिंग डिजिटल ट्रांसफार्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम से चार मैदानी जनपदों में 45 अत्याधुनिक ई-चेक गेट स्थापित किए गए हैं, कई नए डिजिटल प्लेटफार्म लागू किए गए।

- सीएम धामी की सख्त नीति से खनन माफिया पर लगाम, राजस्व में रिकार्ड उछाल
- सीएम धामी की सख्त नीति से खनन माफिया पर लगाम, राजस्व में रिकार्ड उछाल

110 करोड़ का सफर 1217 करोड़ तक पहुंचा

मुख्यमंत्री धामी की पारदर्शी नीतियों के कारण खनन राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2012-13 में मात्र 110 करोड़ रुपये से शुरू हुआ यह सफर अब 2025-26 में 1217 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इससे राज्य को आर्थिक मजबूती मिली है।

स्काच अवार्ड से सम्मानित किया गया

ई-रवन्ना प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए विशेष सिक्योरिटी फीचर युक्त व्यवस्था लागू की गई, जिससे फर्जीवाड़े और दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। इन प्रयासों के चलते अवैध खनन पर लगाम लगी है और राजस्व में कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इन नवाचारों को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रतिष्ठित स्काच अवार्ड से सम्मानित किया गया।

खनन को लेकर धामी सरकार की पारदर्शी नीति पर मुहर

देहरादून : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य में खनन क्षेत्र में बढ़ते राजस्व को धामी सरकार की पारदर्शी

नीतियों का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन को माफिया के चंगुल से मुक्त कर राज्य की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाया गया है। भट्ट ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 950 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 1217 करोड़ रुपये का रिकार्ड राजस्व अर्जित किया गया, जबकि वर्ष 2024-25 में भी 875 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 1041 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। वर्ष 2012-13 में मात्र 110 करोड़ से शुरू हुआ यह सफर अब नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से खनिज नीति और नियमावली का सरलीकरण कर वैध खनन को बढ़ावा दिया गया है, जिससे अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी रोक लगी है। पारदर्शी प्रक्रिया से खनन पट्टों के आवंटन और तकनीकी नवाचारों ने राजस्व वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ई-रवन्ना प्रणाली में सुरक्षा फीचर युक्त कागज लागू कर फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लगाया गया है। (राब्यू)